



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 184 | नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 1974/चैत्र 25, 1896

No. 184 | NEW DELHI, MONDAY, APRIL 15, 1974/CHAITRA 25, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 15th April 1974

S.O. 251(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs. No. S.O. 3609/IDRA/18A/69, dated the 1st September, 1969, read with the Orders of the Government of India, in the late Ministry of Foreign Trade Nos. S.O. 616 dated the 3rd February, 1971 and S.O. 3252, dated the 30th August, 1971, and the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 444(E), dated the 18th August 1973, the management of the industrial undertaking known as New Victoria Mills Company Limited, Kanpur (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period upto and inclusive of the 31st August, 1974;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 245(E) dated the 24th April, 1973 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to Banks and financial institutions and statutory liabilities) to which the said industrial undertaking or

the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended by a further period upto and inclusive of the 31st August, 1974;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2), of section 18FE of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order by a further period upto and inclusive of the 31st August, 1974.

[No. F. 11021/129/72-NTC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1974

का० आ० 251 (अ).—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 616 तारीख 3 फरवरी, 1971 और का० आ० 3252, तारीख 30 अगस्त, 1971 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 3609/आई डी आर ए/18ए/69, तारीख 1 सितम्बर, 1969 और भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 444(ड), तारीख 18 अगस्त, 1973 द्वारा न्यू विक्टोरिया मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन 31 अगस्त, 1974 तक की अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, ग्रहण कर लिया गया है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 245 (ड), तारीख 24 अप्रैल, 1973) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी किए जाने के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों करारों, समझौतों, पंचाटों, स्थायी, आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रतिभूत दायित्वों तथा कानूनी दायित्वों से सम्बन्धित हैं), जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम पर स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्ष-कार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हों, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोदभूत या उदभूत होने वाले सभी अधिकार विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि, 13 अगस्त, 1974 तक की और काला वधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाई जानी चाहिए ;

अतः, अध, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अधि 31 अगस्त, 1974 की और कालावधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[सं० फा० 11021/ 129/ 72-एन टी सी]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव।

